Tripartite Agreement for Clearing Power Dues

*473. DR. T. SUBBARAMIREDDY:††

SHRMATIAMBDCA SONI:

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether the 24 States have signed a tripartite agreement with the Central Government and the Reserve Bank of India to clear dues worth Rs. 37.400 crores;

(b) if so, the main points of the agreement reached;

(c) the total outstanding of State Electricity Boards towards power PSUs like NTPC, NHPC, PGCIL and Coal PSUs, upto September 30, 2001;

(d) whether this arrear has again risen uptil now;

(e) if so, whether this agreement is only for this amount or up-to-date outstanding amount; and

(f) whether any time limit has been fixed for clearing these dues ?

THE MINISTEROF POWER (SHRIANANTGANGARAM GEETE): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The main points of the Tripartite Agreement signed under the Scheme of One Time Settlement of Outstanding Dues of the State Electricity Boards (SEBs) are as follows:

(i) Old arrears of SEBs of the States amounting to Rs. 37,400 crore to 8 CPSUs and Railways as of 30th September, 2001 would be settled as an one-time measure;

(ii) 60% of die interest/surcharge amounting to Rs. 8,300 crore out of the above amount would be waived;

(iii) Thereafter, net outstanding dues of Rs. 29,100 crore would be converted into tax-free Statutory Liquidity Ratio (SLR) bonds with

---

The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.

interest rate of 8.5%per annum which will be repaid over a period of 15 years with the moratorium of 5 years;

(iv) The States will become eligible, to receive incentive amounting to Rs. 6,100 crore over a period of 4 years on adhering to the term and conditions of the agreement;

(v) The Stale Utilities will liave to ensure payment of current bills through Letters of Credit and any defaulted amount would be recovered through adjustment against releases due to the respective State Government on account of Plan Assistance. States' share of Central Taxes and any other grant or loan given to the State by way of debiting their accounts.

(c) The details oftotal outstanding dues of State Electricity Boards towards eight CPSUs namely National Thermal Power Corporation (NTPC). National Hydro-electric Power Corporation (NHPC), Power Grid Corporation of India Ltd. (PGC1L), North-Eastem Electric Power Corporation (NEEPCO) and Damodar Valley Corporation (DVC) under the Ministry of Power, Coal India Ltd. (CIL) and its subsidiaries and Neyveli Lignite Corporation (NLC) under the Ministry of Coal, Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) under the Department of Atomic Energy and the Railways, as on September 30, 2001 are given in the enclosed Statement *(See* below).

(d) Yes Sir.

(e) The Tripartite Agreement covers settlement of old dues to the 8 CPSUs

Wi as on 30-09-2001 by issue of tax-free bonds by the State us concerned and also for recovery of amount defaulted after 30-9-2001, if any, by the SEBs from the Central devolution to the concerned States by debiting their account maintained in the Reserve Bank of India.

(c) In respect of bonds to be issued for sccuritisation of the dues outstanding as on 30-09-2001, after waiver of 60% surcharge, the repayments are to be made by die State Governments *over* a period of 15 years with 8.5% per annum tax-free interest after n moratorium of 5 years on the repayment of principal. In respect of the current bills, payments shall be made within 60 days from the date of billing, or within 45 days of their receipt, whichever is later. Payments made alter this period *sh.'A* attract interest @ 15% per annum compounded

quarterly. Payments that remain outstanding after 90 days from the date of billing shall be recovered, on behalf of the CPSUs by the Ministry of Finance through adjustments against releases due to the respective State Government on account of plan assistance, States' share of Central taxes and any other grant or loan.

Statement

Total Outstanding dues of SEBs payable to 8 CPSUs and Railways as on 30-9-2001.

(Figures in crores of rupees)

SI. No.	Name of CPSU	Principal	Interest	Total
1	2	3	4	5
1	NTPC	10480.49	5384.25	15864.74
2	NHPC	808.55	821.86	1630.41
3.	PGCIL	843.40	252.00	1095.40
4.	DVC	1315.78	1649.52	2965.30
5.	NEEPCO	785.47	374.71	1160.18
6.	NLC	1754.70	845.56	2600.26
7.	<X	4717.13	3046.73	7763.86
8.	NPCIL	2113.00	1465.00	3578.00
9.	Railways	699.72	0.00	699.72
	TOTAL	23518.24	13839.63	37357.87

MR. CHAIRMAN: Question No. 473.

श्री बालकवि बैरागी : सर , आपने जब से इनके बारे में पूछना शुरू किया है, इनके लिए सवाल ज्यादा आने शुरू हो गए हैं , कोई चक्कर हैं । आप इसके बारे में सवाल – जवाब कीजिए ।

SHRJ PREM CHAND GUPTA: Sir, why not fix a quota... *(Interruptions)*

इनका एक फिक्स कर दीजिए।

DR. T. SUBB ARAMIREDDY: They are all fond of me.

(Interruptions) MR. CHAIRMAN: What is the secret behind it ?

एक माननीय सदस्य : शिव भक्ति।

डॉ.टी. सुब्बारामी रेड्डी : जी हां, शिव भक्ति।

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए।

DR. T. SUBB ARAMI REDDY: Sir, I am very happy that the Ministry of Power has entered into an agreement with all the State Governments for the onetime settlement of dues, which amounts to Rs. 37,000 crores. I would like to know what is the modality; what is the time limit; and when you are going to achieve this; and when all the States will be debt free.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, इसके लिए 15 साल का समय निर्धारित किया गया है और इसके परिणाम बहुत ही अच्छे आने लगे हैं। मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। एन.टी.पी.सी. का 2001-02 में जो बकाया था, उसकी रिकवरी 76.7 परसेट थी जो इस साल ,2002-03 के पिछले तीन क्वार्टर्स में, बढ़कर 97.7 परसेंट हो गई है। इसी तरह पावर ग्रिड कारपोरेशन की 2001-02 में 80 परसेंट की रिकवरी थी जो पिछले साल तीन क्वार्टर्स में बढ़कर 99.3 परसेंट हो गई है। इसी प्रकार एन.एच.पी.सी. की रिकवरी है जो 2001-02में 72 परसेंट थी और इस वर्ष पिछले तीन क्वार्टर्स में यह बढ़कर 101 परसेंट हो गई है। इसके जो परिणाम आने हैं, ये बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और जो पुराना बकाया हैं, उसके लिए जो बोनड हम बनाने जा रहे हैं, उसका समय 15 वर्ष का निश्चित किया गया है। सारे राज्यों ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार किया हैं और इसके अच्छे परिणाम होंगे।

DR. T. SUBB ARAMI REDDY: Sir, my second supplementary is: By the year 2001, the outstanding dues from all the States was Rs. 37,500 crores.

As on 4-4-2003, it has gone up to Rs. 45,000 crores. I would like to know, where is the solution, if every year Rs. 8000 or Rs. 10,000 crores keep on increasing. How are we going to solve the problem ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय , इस संदर्भ में केबिनेट ने जो निर्णय लिया , वह निर्णय हुआ मार्च , 2002 में और actually यह tripartite agreement साईन हुआ मार्च ,2003में और 2001 तक का जो बकाया हैं , उसको हम bond के रूप one time settelement में वसूलेगें और उसके बाद का जो है, वह लगभग 6,000 करोड़ केarrears पड़े हैं लेकिन जैसे मैंने पहले आंकड़े दिए तो current bills और arrears ये दोनों ही अब राज्य विद्युत बोर्डो से जो बकाया आना हैं , वह निश्चित रूप में आ है और भविष्य में ये arrears जो हैं , वे भी कम होंगे और रेग्युलर जो उनकी रिकवरी है, करेंट ड्यूज़ हैं , वे निश्चित रूप में regularly मिल पाएंगे ।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir. please allow me to put a supplementary in respect of Question No. 473. Sir, the States are involved.

श्री एस.एस अहलूवालिया : नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुला लिया सर ।

श्री सभापति : पूछने दीजिए । आप छोटा ही पूछना क्योंकि मेरे पांच क्वेश्चन बाकी पड़े हैं ।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, how to liquidate the dues of the SEBs, that is the agenda before the nation. I can understand that. But there is another small story to that. There are many sick Central public sector undertakings located in different States. They have got the dues of the SEBs. The SEBs are not being paid. I want to know whether the Minister would like to assure that if someone is not in a position to pay

प्लान एसिस्टेंस से पैसा कट रहा हैं , स्टेट से । स्टेट को पैसा नहीं दे रहें हैं । इसी तरह से स्टेट प्लान एसिस्टेंस में यह जोड़ दिया जाएगा कि जिस स्टेट में सैन्ट्रल पब्लिक सैक्टर यूनिट्स एसईबीज को पैसा नहीं दे पा रहे हैं , डी वी सीज को पैसा नहीं देपा रहा हैं इसको दुर्गापुर फर्टिलाजर पावर को...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी : पैसा नहीं है, How that money is going to be recovered ? How is the Minister going to recover that money ? .... *(Interruptions)....*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सर, राज्य सरकारों को सहायता तो दी जा रही हैं। राज्य सरकारों से यूटिलिटी से वह धन जाने की आवश्यकता है । कई राज्यों से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो धन केन्द्र की ओर से राज्य सरकारों को , इस यूटिलिटी को सुधारने के लिए दिया जा रहा है, वह समय पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से उन्हें निरंतर ये सूचनाएं दी जा रही हैं जो भी धन हम राज्य विद्युत बोर्डो की सेहत सुधारने के लिए दे रहे हैं .....(व्यवधान)....

श्री दीपांकर मुखर्जी : यह क्वेश्चन नहीं है। आपका सैन्ट्रल गवर्नमेंट का पैसा बकाया है SEBS के पास DVCS के पास,CEBs के पास। सिक जैसे इनकी कम्पनी है। NTC ऐसे सिक मिल्स का जो ड्यूज है, वह बकाया है SEBS को लोस हो रहा हैं तो वह पैसा जब सिक सैन्ट्रल पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं दे पा रही हैं तो प्लान एसिस्टेंस में वह पैसा जोड़कर उनको दीजिए । SEBS का अगर पैसा बकाया है तो आप प्लान एसिस्टेंस से काटेंगे और उनको सैन्ट्रल गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स से जो पैसा मिलने वाला है, वह पैसा कौन देगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय ?

श्री सभापति : बताइए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, इस प्रश्न का सीधा संबंध मेरे ऊर्जा मंत्रालय से नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : क्यों नहीं हैं । आप उनसे पैसा क्यों काट रहे हैं । ...(व्यवधान)... स्टेट का आप पैसा ले रहे हैं। स्टेट को जो पैसा मिलने वाला हैं वह नहीं दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Next question.

SHRIDIPANKAR MUKHERJEE : Sir, someone should reply to that ? *...(Interruptions)* ... इसका उत्तर आना चाहिए। ...(व्यवधान)...